सिविल अपील

न्यायमूर्ति एस.बी. कपूर और आर.एस. नरूला से पहले

मनोहर लाल और अन्य, अपीलकर्ता।

बनाम

गणेशी राम और अन्य,- प्रतिवादी।

1958 की नियमित प्रथम अपील संख्या 456

16 सितम्बर 1968.

सूदखोर ऋण अधिनियम (1918 का X) पंजाब ऋण राहत अधिनियम (1934 का VII) द्वारा संशोधित - एस. 3 परंतुक (ii) शब्द "डिक्री" - चाहे सहमति डिक्री शामिल हो - अदालतें - क्या मोचन के लिए बाद के मुकदमे में पिछली सहमति डिक्री के आधार पर देय ऋण लेनदेन को फिर से खोल सकते हैं। 'सिविल प्रक्रिया संहिता (में *का* 1908)- *एस।* 11- *समझौता डिक्री- चाहे पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करता हो।*

आयोजित, सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के दायरे में राहत का आह्वान उस उप-धारा के दूसरे प्रावधान के अधीन है और उस प्रावधान में "डिक्री" शब्द उतना ही लागू होता है न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर डिक्री के रूप में सहमति डिक्री। समझौते पर आधारित एक डिक्री एक तरह से संबंधित मुद्दों पर पार्टियों की स्वीकृति पर पारित की जाती है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रतियोगिता के बाद प्राप्त डिक्री के समान ही बल रखती है। सिविल न्यायालयों के पास पिछले सहमति डिक्री के आधार पर देय बंधक धन के संबंध में लेनदेन को फिर से खोलने या ऋण को कम करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह उक्त पिछले डिक्री को प्रभावित नहीं कर सकता है। (8 के लिए).

आयोजित, समझौता डिक्री न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा किसी चीज़ की स्वीकृति है, जिस पर पक्ष सहमत हैं। एक समझौता डिक्री केवल पक्षों के समझौते पर न्यायालय की मुहर लगाती है। कोर्ट ने पहले चरण में समझौता डिक्री पारित करते हुए कुछ भी तय नहीं किया है। यह केवल न्यायालय का निर्णय है जो हो सकता है *बस इसीलिये,* चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत वैधानिक हो या सार्वजनिक नीति के मामले में रचनात्मक। इसलिए यह एक का निर्णय है *आर ई* के सिद्धांतों पर एक बाधा के रूप में कार्य करता है *बस इसीलिये* चाहे वैधानिक हो या रचनात्मक. जब यह पाया जाता है कि वास्तव में किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान संबंधित मुद्दे की सुनवाई पर रोक नहीं लगाते हैं और समझौते पर आधारित डिक्री कार्य नहीं करेगी। *बस इसीलिये* उस मुद्दे की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए।

(पैरा 5 और 6)।

श्री मोहन लाल जैन, उप न्यायाधीश के न्यायालय की डिक्री से प्रथम अपील 1st *क्लास,रोहतक, दिनांक* 25*अगस्त का वां दिन,* 1958,*वादग्रस्त भूमि को न्यायालय में जमा करने की शर्त पर वादी को कब्जे की डिक्री प्रदान करना।* रु. 6,000*डिक्री की तारीख के एक महीने के भीतर, ऐसा न करने पर उनका मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा।*

डीइसे लेंसीहाथजीयूपीटीए औरजे. वी.जीयूपीटीए, एवकील, के लिएअपीलकर्ता।

जी. पी. जैन, सत्य प्रकाश जैन और जी. सी. गर्ग, अधिवक्ता, केवल प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

अन्य उत्तरदाता, एनभावनाएं.

प्रलय

न्यायमूर्ति एनबात करना.- एकमात्र प्रश्न जो इस वादी में निर्णय की मांग करता है वह श्री मोहन लाई जैन, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहतक के न्यायालय के 25 अगस्त, 1958 के फैसले के खिलाफ नियमित प्रथम अपील है, जिसमें वादी-अपीलकर्ताओं को डिक्री प्रदान की गई थी।

विवादग्रस्त भूमि का कब्ज़ा न्यायालय में रु. की राशि जमा करने की शर्त पर दिया जाएगा। बंधक भूमि के मोचन के लिए डिक्री की तारीख * के छह महीने के भीतर 6,000 - चाहे बंधक संपत्ति के मोचन के लिए बाद के मुकदमे में वादी-बंधककर्ता से प्रतिवादी बंधक पर मुकदमे में बंधक के कारण देय राशि का प्रश्न हो, कौन सा प्रश्न पिछले मुकदमे में पहले ही तय किया जा चुका है *अंतर पक्ष,* जिसके आधार पर न तो बंधक भूमि को छुड़ाया गया है और न ही बंधक को जब्त किया गया है, उसे सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 के तहत फिर से खोला जा सकता है *जैसा* पंजाब ऋण राहत अधिनियम (1934 का 7) द्वारा संशोधित। यह प्रश्न निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में उठा है:-

2. मुकदमे में भूमि 1 को प्रतिवादी संख्या 2 से 11 के पूर्ववर्ती-हित में गणेशी लाई पर कब्जे के साथ रुपये में गिरवी रख दिया गया था। वर्ष 1921 में 4,000 रु. की ब्याज राशि के विरुद्ध भूमि का उपभोग समायोजित किया जाना था। 200 जो ब्याज की राशि बंधक धन के आधे पर गिर गई, यानी, रुपये पर। 2,000. शेष बंधक-राशि रु. 2,000 रुपये पर ब्याज देना था। प्रति माह 0-7-9 प्रतिशत. मूल गिरवीदार की मृत्यु के बाद, उसके उत्तराधिकारियों ने अपने गिरवीदार अधिकार घासी राम, प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में रुपये की राशि में बेच दिए। 3,000. वादी अपीलकर्ता (जिनका संदर्भ इस फैसले में ट्रायल कोर्ट में उनके शीर्षक के साथ-साथ इस मुकदमे के अन्य पक्षों के लिए भी किया जाएगा) जो 9 मई, 1955 को प्राप्त मूल गिरवीकर्ता गणेशी लाई

के उत्तराधिकारी हैं। रुपये के भुगतान पर विवादग्रस्त भूमि को छुड़ाने का आदेश। डिक्री की तारीख से छह महीने के भीतर उन्हें 6,000 रुपये जमा करने होंगे। सक्षम सिविल न्यायालय के 9 मई, 1955 के फैसले में आगे प्रावधान किया गया कि यदि वादी छह महीने की उपरोक्त अवधि के भीतर राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो "बंधक पहले की तरह जारी रहेगा।" यह दोनों पक्षों का स्वीकृत मामला है कि पिछले मुकदमे में सिविल कोर्ट की सहमति डिक्री द्वारा निर्धारित बंधक राशि का भुगतान वादी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर या उसके बाद किसी भी समय नहीं किया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादियों ने बंधक को जब्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह उपर्युक्त परिस्थितियों में था कि जिस मुकदमे से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है, वह वादी द्वारा 5 अगस्त, 1957 को दायर किया गया था, जिसमें किसी भी बंधक राशि के भुगतान के बिना या भुगतान के बिना विवाद में भूमि को छुड़ाकर कब्जे की डिक्री का दावा किया गया था। बंधक धन जो भूमि से होने वाले लाभ का हिसाब लेने के बाद कानून के अनुसार तय किया जा सकता है। मुक़दमे का प्रतिवादी नंबर 1 घासी राम ने अकेले विरोध किया था» अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही की गई*पक्षपातवाला।* प्रतिवादी संख्या 1 ने बंधक के साथ-साथ इसकी शर्तों को भी स्वीकार किया। हालाँकि, उन्होंने दलील दी कि वादी का दावा सिद्धांतों पर वर्जित है *मामले का निर्णय किया गया* एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पिछले निर्णय के कारण, और वादी द्वारा उक्त पिछले डिक्री द्वारा अनुमत समय के भीतर अपेक्षित भुगतान करने पर भूमि को छुड़ा नहीं पाने के कारण। प्रतिवादी ने दलील दी कि इसके परिणामस्वरूप बंधक का स्वत: फौजदारी हो गया है। विकल्प में यह दलील दी गई कि किसी भी मामले में वादी बंधक धन की मात्रा को चुनौती नहीं दे सकते, जिसका भुगतान वे करने के लिए उत्तरदायी थे, यानी, रु। 6,000 जो पिछले मुकदमे में न्यायालय द्वारा पाया गया था, और इसलिए, वादी प्रतिवादी से हिसाब नहीं मांग सकते थे। पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने सात मुद्दे तय किए, जिनमें से हम इस अपील में केवल मुद्दे नंबर 2 और 3 से संबंधित हैं, जो थे: -

"2. क्या मुकदमा वर्जित है *बस इसीलिये*?

3. क्या वादी रुपये की राशि को चुनौती दे सकते हैं? पिछले मुक़दमे में पक्षों के बीच हुई सहमति के अनुसार 6,00$?"

3. अपील के तहत अपने फैसले और डिक्री द्वारा, 1 ट्रायल सी ने प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दा नंबर 2 पाया और माना कि मोचन के लिए मुकदमा वर्जित नहीं था *बस इसीलिये,* लेकिन वाद संख्या 3 का फैसला वादी के खिलाफ कर दिया और माना कि वादी पिछले मुकदमे में सक्षम न्यायालय के फैसले की मांग नहीं कर सकते, हालांकि यह समझौता फिर से खोले जाने पर आधारित है। बंधक राशि की वह राशि जो वादी विवाद में भूमि के मोचन के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। मुद्दा संख्या 3 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं होने पर, अन्यथा सफल वादी ने इस न्यायालय में इस अपील को प्राथमिकता दी है।

दिसम्बर एल को अपील स्वीकार करते हुए। 1958, दुआ, जे. ने वादी-अपीलकर्ताओं के आवेदन पर निर्देश दिया कि रुपये की राशि। प्रश्नगत 6,000 रुपये उनके द्वारा न्यायालय में जमा किए जा सकते हैं और गिरवीदार-प्रतिवादियों को प्रश्नगत राशि की बहाली के लिए निष्पादन न्यायालय की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने पर राशि वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। प्रतियोगी पक्षों के विद्वान वकील ने हमें सूचित किया कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, वादी ने ट्रायल कोर्ट में अपेक्षित राशि जमा कर दी है और इसके परिणामस्वरूप बंधक भूमि का वास्तविक कब्जा पहले ही प्राप्त कर लिया है। अपील के तहत डिक्री इस न्यायालय के निर्णय के अधीन है। श्रीमान। प्रतिवादी-प्रतिवादी के तत्कालीन विद्वान वकील श्री गंगा प्रसाद जैन ने मुद्दे संख्या 2 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया और वास्तव में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वादी के मोचन के बाद के मुकदमे पर रोक नहीं थी। . इसलिए, पार्टियों ने हमारे सामने केवल मुद्दे नंबर 3 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की शुद्धता या अन्यथा के बारे में विवाद किया, वादी-वी अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री दलीप चंद गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि मोचन के लिए पिछले मुकदमे में डिक्री पार्टियों के बीच समझौता होने के बाद, निचली अदालत बाद के मुकदमे के प्रयोजनों के लिए इसे अनदेखा करने के लिए बाध्य थी, जिसमें पूरे मामले को फिर से खुला माना जाना चाहिए। वादी वास्तव में दावा करते हैं कि अदालत सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 के तहत बंधक ऋण को कम करने के लिए बाध्य है और पिछला डिक्री ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है - उन्होंने आगे तर्क दिया कि बंधक धन की मात्रा का निर्धारण किया गया था नहीं*आर ई* जिस पर न्यायालय ने पिछले मुकदमे में ही फैसला सुनाया था, और वास्तव में जो हुआ था वह यह था कि ट्रायल कोर्ट ने केवल बंधक धन की मात्रा के बारे में पार्टियों के बीच एक समझौते पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि पिछले मुकदमे की पूरी डिक्री को एक अविभाज्य इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और जिस क्षण वादी ने उक्त डिक्री द्वारा अनुमत समय के भीतर बंधक को नहीं भुनाया, तो पिछली पूरी डिक्री को एक अविभाज्य इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। ख़त्म कर दिया गया है, और वर्तमान मुक़दमे की सुनवाई ऐसे की जानी चाहिए थी जैसे कि पिछले मुक़दमे में कोई डिक्री पारित नहीं की गई थी। वकील ने सबसे पहले प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला दिया-*रघुनाथ सिंह व अन्य* बनाम हंसराज कुंवर और दूसरे (1). उस मामले में यह माना गया था कि जब तक यह नहीं कहा जा सकता कि डिक्री में इस आशय का निर्णय शामिल है कि गिरवीकर्ता का छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो गया है, तब तक यह कार्य नहीं कर सकता है *बस इसीलिये* ताकि अदालत को, सिविल प्रक्रिया न्यायालय की धारा 11 के तहत, दूसरे मोचन मुकदमे की कोशिश करने से रोका जा सके। प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं है *रघुनाथ सिंह का मामला* (सुप्रा) और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा निर्धारित कानून के वाई प्रस्ताव

पर एक पल के लिए भी हमला नहीं किया। पिछले मुकदमे में बंधक धन की मात्रा के संबंध में न्यायालय के निर्धारण को फिर से खोलने के बारे में कोई प्रश्न नहीं है *रघुनाथ सिंह और अन्य का मामला.* सन्दर्भ था

फिर मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार किया गया *कीसारी संतम्मा* में। *कनुमाथा रेड्डी वेंकटराम रेड्डी और अन्य* (2), जिसमें यह माना गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के आवेदन के संबंध में, विभाजन के लिए एक मुकदमे को अलग तरह से माना जाना चाहिए, और उसी संपत्ति के विभाजन के लिए एक बाद के मुकदमे को पिछले मामले में शामिल किया जाना चाहिए। आदेश 23 नियम 1 के तहत पिछले मुकदमे को खारिज करने से मुकदमा वर्जित नहीं है, भले ही समझौता के आधार पर पिछले मुकदमे को खारिज कर दिए जाने पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं ली गई थी, इसका कारण यह है कि मुकदमा लाने का अधिकार अन्य मुकदमों के विपरीत विभाजन एक सतत अधिकार है, और जैसे ही प्रतिवादी समझौता करने में विफल रहता है, "पार्टियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि वे समझौते से पहले मौजूद थे।" हालाँकि मुख्य प्रश्न माधवन नायर, जे. द्वारा तय किया गया था *केसारी संतम्मा का मामला*(सुप्रा) हमारे समक्ष अपील में विवाद में नहीं है, श्री दलीप चंद गुप्ता ने विद्वान न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर अधिक जोर दिया है कि समझौता न करने की स्थिति में क्या होता है कि "पक्ष उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है क्योंकि वे समझौते से पहले मौजूद थे।" मामले में अपने फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस्तेमाल की गई उपरोक्त अभिव्यक्ति से *कीसारी संतामा की,* वकील यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछले मुकदमे में डिक्री के निष्पादन या अनुसरण में वादी द्वारा विवाद में भूमि को छुड़ाने का परिणाम यह है कि हमारे समक्ष पक्षकारों को भी उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है क्योंकि वे समझौते से पहले मौजूद थे। जिसका मतलब यह होगा कि समझौते के साथ-साथ उस पर पारित डिक्री को पूरी तरह से नजरअंदाज करना होगा और इसके परिणामस्वरूप पिछले मुकदमे में बंधक धन का निर्धारण अस्तित्वहीन माना जाएगा। हमें विद्वान वकील के इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता। मामले का एकमात्र पहलू जिससे मद्रास उच्च न्यायालय चिंतित था, विभाजन के लिए बाद के मुकदमे की स्थिरता के बारे में था। हमारे समक्ष मुद्दा संख्या 3 में शामिल विवरण जैसा कोई प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था। जिस अवलोकन का संदर्भ श्री दलीप चंद गुप्ता ने किया है, वह केवल इस बात पर जोर देने के उद्देश्य से किया गया था कि विभाजन के मुकदमे को इस आरोप पर खारिज नहीं किया जाएगा कि इसे समायोजित किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है जो समझौते से पहले मौजूद थे और उक्त सिद्धांत को प्रभावी करने से यह निष्कर्ष निकलेगा कि बाद का मुकदमा कायम रखने योग्य था। जो कुछ भी माना गया वह यह था कि मद्रास न्यायालय के समक्ष मामले में पिछले मुकदमे को खारिज करना वादी के मुकदमे में बाधा के रूप में काम नहीं कर सकता था। में निर्णय का अनुपात *की सारी संतम्मा का मामला* श्री दलीप चंद गुप्ता के विवाद को आगे बढ़ाने की बिल्कुल भी अपील नहीं करता।

5. सुप्रीम कोर्ट में अपने आधिपत्य की घोषणा करने वाले प्राधिकारी श्री गुप्ता द्वारा अंतिम स्थान पर रिलायंस को 5वां स्थान दिया गया। पुलवर्थी वेंकता सुबहा राव एंड ऑथर्स बनाम *वल्लूरी जगन्नाध राव और अन्य* (3). उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले का भाग्य एसपीओपीओ और मद्रास कृषक राहत अधिनियम (1938 का 4) की धारा 19 के वास्तविक निर्माण पर निर्भर था, जिसे मद्रास कृषक राहत (संशोधन) अधिनियम (23) की धारा 16(ii) द्वारा संशोधित किया गया था। 1948 का)। अनुभाग की उपधारा (1). 1938 मद्रास अधिनियम के 19, अंतर*आलिया,* बशर्ते कि जहां किसी न्यायालय ने उस अधिनियम के लागू होने से पहले एक डिक्री पारित कर दी हो। एक कृषक के विरुद्ध ऋण की अदायगी के लिए न्यायालय, एक आवेदन पर विचार करेगा। निर्णय-देनदार उस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसी डिक्री पर लागू करता है और सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी भी बात के बावजूद, तदनुसार डिक्री में संशोधन करता है या उसकी संतुष्टि दर्ज करता है, जैसा भी मामला हो- धारा l9 की उप-धारा (2) प्रावधान करती है उप-धारा (1) उन मामलों पर भी लागू होती है जहां अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर देय ऋण के संबंध में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है। 1943 के संशोधन अधिनियम की धारा 16 में कहा गया है कि उक्त 1948 अधिनियम द्वारा संशोधन मोड निम्नलिखित पर लागू होगा। कार्यवाहियों के कुछ अंश, अर्थात्:-

फाई) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद शुरू किए गए सभी मुकदमे और कार्यवाही;

. (ii)- इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले संस्थित सभी मुकदमे और कार्यवाही। जिसमें कोई डिक्री या आदेश पारित नहीं किया गया है, या जिसमें पारित डिक्री या आदेश ऐसे प्रारंभ से पहले अंतिम नहीं है;

(iii) सभी थूक और कार्यवाही जिसमें पारित डिक्री या आदेश शुरू होने से पहले पूर्ण रूप से निष्पादित या संतुष्ट नहीं किया गया हैकायहकार्यवाही करना।

(3) (1964) 2 एस.सी.आर. 310. मद्रास अधिनियम के प्रासंगिक मूल प्रावधान निर्णय-देनदारों को अधिकार देते हैं जिनके खिलाफ धारा 16 के अंतर्गत आने वाले डिक्री पारित किए गए हैं ताकि उन्हें कम करने के लिए आवेदन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए उठने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि क्या अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले शुरू किए गए मुकदमे में पारित समझौता डिक्री संशोधन अधिनियम की धारा 16 के खंड (ii) या खंड (iii) के अंतर्गत आती है। . उच्चतम न्यायालय ने कहा:-

"सहमति के बाद पारित डिक्री और समझौते पर पारित डिक्री के बीच कोई अंतर नहीं होने के कारण, धारा 16 के खंड (ii) में जिन शब्दों में पारित डिक्री या आदेश अंतिम नहीं हुआ है, उन्हें समझौता डिक्री के

संदर्भ में नहीं माना जा सकता है। वे डिक्री जो अंतिम होती हैं जैसे बंधक पर मुकदमे में फौजदारी आदि के लिए अंतिम डिक्री।"

उनके आधिपत्य ने उनके समक्ष सहज तथ्यों पर कायम रखा कि यह मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पढ़ी गई धारा 16 के खंड (iii) द्वारा शासित था और निर्णय-देनदार, इसलिए, इसका उल्लंघन करने के हकदार थे। एक बार फिर डिक्री को कम करने का सवाल. निर्णय के जिस भाग पर श्री गुप्ता ने भरोसा किया है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि यद्यपि पहले अवसर पर दावे की राशि में कमी के लिए दबाव डालने में निर्णय-देनदारों का आचरण महत्वपूर्ण था , इसका गठन नहीं हुआ *बस इसीलिये* या तो वैधानिक या रचनात्मक। यह उस संदर्भ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि समझौता डिक्री अदालत द्वारा एक निर्णय नहीं था, बल्कि अदालत द्वारा उस चीज़ की स्वीकृति थी जिस पर पक्ष सहमत थे, और एक समझौता डिक्री केवल अदालत की मुहर लगाती है पार्टियों के समझौते पर. उस आधार पर यह माना गया कि न्यायालय ने पहले चरण में समझौता डिक्री पारित करते समय कुछ भी निर्णय नहीं लिया था, और यह केवल न्यायालय का एक निर्णय था जिसे *बस इसीलिये,* चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत वैधानिक हो या सार्वजनिक नीति के मामले में रचनात्मक। सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने यह दिखाने के लिए सबूतों पर गौर करने से इनकार कर दिया कि निर्णय-देनदार ने वास्तव में सहमति डिक्री के तहत दो रकम का भुगतान किया था क्योंकि उस मामले में आचरण द्वारा रोक की कोई याचिका नहीं उठाई गई थी या कोशिश नहीं की गई थी। श्री गुप्ता का तर्क यह था कि एक निर्णय-ऋणी निस्संदेह पंजाब ऋण राहत अधिनियम (1934 का 7) की धारा 5 द्वारा संशोधित सूदखोर ऋण अधिनियम (1918 का 10) की धारा 3 के प्रावधानों को लागू करने का हकदार है। . ऐसे मामले में जहां का अनुदान

उस प्रावधान के तहत राहत किसी न्यायालय के किसी भी डिक्री को प्रभावित करेगी, लेकिन पुलवर्ती वेंकट सुभा राव के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणियों के आलोक में पहले की सहमति डिक्री को न्यायालय का डिक्री नहीं कहा जा सकता है। . विद्वान वकील के इस तर्क की सराहना करने के लिए, पंजाब अधिनियम 7, 1934 द्वारा संशोधित सूदखोर दान अधिनियम की धारा 3 के प्रासंगिक भाग पर इस स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा से प्रासंगिक उद्धरण उद्धृत किया गया है नीचे : -

"(1) सूदखोरी कानून निरसन अधिनियम, 1855 में किसी भी बात के बावजूद, जहां, किसी भी मुकदमे में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, चाहे सुना गया हो *पक्षपातवाला* या अन्यथा, न्यायालय के पास विश्वास करने का कारण है,-

a. कि ब्याज अत्यधिक है; और
b. यह कि लेन-देन, उसके पक्षों के बीच, काफी हद तक अनुचित था, न्यायालय निम्नलिखित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अर्थात्, -

i. लेन-देन को फिर से खोलें, पार्टियों के बीच हिसाब-किताब करें और देनदार को किसी भी अत्यधिक ब्याज के संबंध में सभी देनदारियों से मुक्त करें;
ii. किसी भी समझौते के बावजूद, पिछले लेनदेन को बंद करने और एक नया दायित्व बनाने के लिए, उनके बीच पहले से ही लिए गए किसी भी खाते को फिर से खोलें और देनदार को किसी भी अत्यधिक ब्याज के संबंध में सभी देनदारियों से राहत दें, और यदि खाते के संबंध में कुछ भी भुगतान किया गया है या अनुमति दी गई है ऐसी देनदारी, लेनदार को किसी भी राशि को चुकाने का आदेश देगी जिसे वह उसके संबंध में चुकाने योग्य मानता है;

जी. पी. जैन, सत्य प्रकाश जैन और जी. सी. गर्ग, ए, केवल प्रतिवादी नंबर 1 के वकील हैं।

प्रलय

(बी) उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपात पुलवर्थी वेंकता सुबहा राव केस (3), हमारे समक्ष इस मामले का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह केवल एक का निर्णय है*आर ई* के सिद्धांतों पर एक बाधा के रूप में कार्य करता है*बस इसीलिये* चाहे वैधानिक हो या रचनात्मक. जब यह पाया जाता है कि वास्तव में किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान संबंधित मुद्दे की सुनवाई पर रोक नहीं लगाते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को असफल होना चाहिए, सामान्य सिद्धांतों के कारण नहीं*बस इसीलिये*, लेकिन इस तथ्य के कारण कि ऋण को फिर से खोलने या कम करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से उसी प्रावधान द्वारा वर्जित किया गया है जिसे अपीलकर्ता प्रासंगिक राहत प्राप्त करने के लिए लागू करना चाहते हैं। सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 का प्रासंगिक हिस्सा यह कहता है कि न्यायालय धारा 3 की उपधारा (1) के तहत किसी भी लेन-देन को फिर से नहीं खोलेगा या कोई राहत नहीं देगा, जहां ऐसा करने से "न्यायालय का कोई भी आदेश प्रभावी होता है। सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक (ii) में अभिव्यक्ति "न्यायालय की कोई भी डिक्री", मेरी राय में, एक सहमति डिक्री पर उतनी ही लागू होती है जितनी कि एक विवादित कार्रवाई में पारित डिक्री पर। . यह धारा 11 के प्रावधानों या सिद्धांतों के विपरीत हैकासिविल प्रक्रिया संहिता, जो केवल ऐसे मुद्दे की सुनवाई पर रोक लगाती है जो पिछले मुकदमे में प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से मुद्दा था और जिस पर सक्षम न्यायालय का निर्णय आरोपित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या वर्तमान मामले में अपीलकर्ता धारा 3 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक की रोक से बच सकते हैं, सरल प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है - "क्या किसी राहत के अनुदान के परिणामस्वरूप कटौती होगी रुपये की राशि का. पिछले डिक्री के तहत देय 6,000 पिछले डिक्री को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। वह प्रश्न पूछना उसका उत्तर देना है। उपरोक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर मुझे असंभव प्रतीत होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में मद्रास अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान स्पष्ट रूप से डिक्रीटल ऋणों को कम करने का प्रावधान करते हैं। 1934 के पंजाब अधिनियम द्वारा संशोधित सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 के तहत

किसी भी ऋण को कम करने का पंजाब में सिविल न्यायालयों को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सिवाय धारा 3 में उल्लिखित परिस्थितियों के। इस संबंध में मेरे द्वारा 1934 के पंजाब अधिनियम के भाग IV में निहित विभिन्न धाराओं का कोई संदर्भ नहीं दिया जा रहा है, जिसे बाद में ऋण सुलह बोर्डों के समक्ष कार्यवाही से संबंधित संशोधित किया गया है - क्योंकि वे इस अपील पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजाब के सिविल न्यायालयों में उपलब्ध राहत उस धारा की उप-धारा (1) के प्रावधान (i) और प्रावधान (ii) के अधीन है। यह मामला पूरी तरह से परंतुक (ii) के अंतर्गत आता है। न ही हमें श्री गुप्ता के इस तर्क में कोई दम नजर आता है कि पिछली डिक्री के छह महीने के भीतर वादी द्वारा बंधक राशि का भुगतान न करने से डिक्री उप-के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए अस्तित्वहीन हो गई। सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 की धारा (1)। प्रासंगिक प्रावधान यह नहीं कहता है कि यह केवल एक निष्पादन योग्य डिक्री है जिसके प्रभाव से उस धारा की उप-धारा (1) के दायरे में राहत की उपलब्धता बाधित होगी। परंतुक द्वारा किसी न्यायालय के किसी भी डिक्री का प्रभाव निषिद्ध है।

7. प्रतिवादी प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री गंगा प्रसाद जैन ने हमें अवध मुख्य न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया।दर्शन लाए और दूसरे बनाम *मुनु सिंह* (4), जिसमें यह माना गया है कि पूर्व डिक्री के रूप में कार्य करता है*बस इसीलिये* बंधक पर देय राशि के प्रश्न पर और मोचन की इक्विटी का क्रेता पूर्व डिक्री द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान पर मोचन का हकदार है। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि पूर्व डिक्री एक सहमति डिक्री थी या प्रतियोगिता के बाद प्राप्त डिक्री थी *दर्शन लाए* , (सुप्रा)। तब प्रतिवादी की ओर से लाहौर उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा रखा गया था*फूला सिंह*वी बर*चंद एवं अन्य* (5). इस मामले का वास्तव में अवध न्यायालय द्वारा पालन किया गया था.. लाहौर मामले में यह माना गया था कि विचाराधीन बंधक पर देय राशि का प्रश्न था*बस इसीलिये* पिछले मुकदमे में डिक्री के कारण। बॉम्बे हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक हुई रामजी वल्द बापूजी बनाम *पंढरी-नाथ वलाड रावजी और अन्य* (6) (स्कॉट, सी.जे. के अनुसार), कि "दूसरे मोचन मुकदमे को पिछले मोचन डिक्री के बाध्यकारी प्रभाव को पहचानना चाहिए*कुछ* जहाँ तक वह उस डिक्री की तारीख तक खातों का निपटान करता है, और दूसरे मुकदमे में न्यायालय का कर्तव्य दूसरे मुकदमे या डिक्री की तारीख पर देय राशि का पता लगाने और ऐसे परिणामी देने तक सीमित होगा। कानून अनुमति के अनुसार राहत।" में*माउंट मैना बीबी और अन्य* बनाम चौधरी वकील अहमद और दूसरा (7), (पेज 68 पर), यह माना गया कि

4. वायु। 1940 \- 273
5. ए.जे.आर. 1917 लाह. 446.
6. आई-एल.आर. 43 अच्छा 334.
7. वायु। 1925 पी.सी. 63.

मेहर ऋण की राशि और ब्याज की दर का प्रश्न जो पहले मुकदमे में तय किया गया था, उसे दूसरे मुकदमे में फिर से नहीं खोला जा सकता था, और यह केवल पिछले डिक्री की तारीख के बाद की राशि थी जो हो सकती थी बाद के चरण में चला गया। प्रिवी काउंसिल द्वारा यह देखा गया कि पहले के मुकदमे में डिक्री से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने से वादी का उत्तराधिकार का अधिकार, या भविष्य में किसी समय भूमि पर कब्ज़ा वापस पाने का उनका अधिकार समाप्त हो गया।

8. श्रीमान गंगा पार्षद जैनिथ जैन ने अंततः हैरिस और गंगा नाथ, जे.जे. के दिव्य पीठ के फैसले का हवाला दिया।*इबनी हसन* बनाम गुलकंदी लाए और दूसरा (8). उस मामले में यह माना गया था कि जहां उच्च न्यायालय के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पहले पारित डिक्री को प्रभावित किए बिना ब्याज को कम करना संभव नहीं है, वह सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हैउसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो किसी डिक्री को प्रभावित करता हो, चाहे डिक्री कोई भी हो*अंतर पक्ष* या नहीं। एक बार जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए भेद को मान्यता मिल जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धांतों के अनुप्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून*बस इसीलिये* सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के आवेदन के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। धारा 3 की उपधारा (1) के दायरे में राहत उस मामले में भी नहीं दी जा सकती जहां कुछ डिक्री नहीं हैं*अंतर पक्ष* प्रभावित होने की संभावना है. एक सहमति डिक्री जो है *पार्टियों के बीच* निश्चित रूप से किसी ऐसे डिक्री से कमतर स्थान पर नहीं रखा जा सकता जो समतामूलक नहीं है *अंतर पक्ष.* जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जरूरी नहीं कि किसी विवादित कार्रवाई में न्यायालय का निर्णय ही दूसरे प्रावधान के तहत रोक बनाता है। यह किसी भी सक्षम न्यायालय की किसी भी डिक्री को प्रभावित करने की संभावना है जो संबंधित बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए, हम मुद्दे संख्या 3 पर ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय में कोई गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उस तर्क से निपटना अनावश्यक है जिस पर ट्रायल कोर्ट ने उस मुद्दे पर अपना निष्कर्ष आधारित किया था। इसलिए, हम यह मानेंगे कि सूदखोर ऋण अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के दायरे के तहत राहत का आह्वान उस उप के दूसरे प्रावधान के अधीन है।अनुभाग और उस परंतुक में "डिक्री" शब्द उतना ही लागू होता है
8. वायु। 1936 सभी. 611.न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर एक सहमति डिक्री के रूप में। समझौते पर आधारित डिक्री एक तरह से संबंधित मुद्दों पर पार्टियों की स्वीकृति पर पारित की जाती है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रतियोगिता के बाद प्राप्त डिक्री के समान ही बल रखती है। इस मामले की परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं को बंधक धन के संबंध में दी गई कोई भी राहत, जो पिछली सहमति डिक्री की तारीख पर देय थी, उक्त पिछली डिक्री को प्रभावित नहीं कर सकती है।

9. इस मामले में हमारे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है, वादी की अपील विफल हो जाती है और तदनुसार लागत सहित खारिज कर दी जाती है।

न्यायमूर्ति एस.बी. कपूर,.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा